"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 823]

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2024 — अग्रहायण 28, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

F. No. 4555 / 4467 / XXI-B/2024.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 2006 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- 1. नियम 6 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 - ''(3) ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'' की धारा 34 के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित होंगी:—
 - (क) "अल्प दृष्टि" और "दृष्टि बाधित" व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत।
 - (ख) "बधर" को छोड़कर "श्रवण बाधित" व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत।
 - (ग) ''चलन, निःशक्तता'', 'कुष्ठ रोग से मुक्त'', ''बौनापन'', ''तेजाब आक्रमण से पीड़ित'', ''प्रमस्तिष्क घात'' और ''पेशीय दुष्पोषण'' वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत।
 - (घ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किये गये पदों में खण्ड (क) से खण्ड (ग) के अधीन व्यक्तियों में से ''स्वपरायणता'' और ''बहृदिव्यांगता'' वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत।
 - (ड़) सेवा में भर्ती में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगता का प्रतिशत इस संबंध में समय—समय पर जारी राज्य सरकार के कार्यकारी निर्देशों / नियमों / परिपत्रों के अनुसार होगाः

परंतु जहाँ किसी भर्ती वर्ष में संदर्भित दिव्यांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, यदि कोई रिक्ति भरी नहीं जा सकेगी, तो ऐसी रिक्ति, पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में अग्रनीत होगी और यदि पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होते है, तो पहले यह चार प्रवर्गो में से अदला—बदली द्वारा हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी उस पद, के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोक्ता, दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगाः

परंतु यह और कि यदि किसी स्थापना में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है, कि दिये गये प्रवर्ग के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता, तो ऐसी रिक्तियों को समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त चार प्रवर्गों में अदला बदली की जा सकेगी।"

2. नियम 11 के उप—नियम (3) में, शब्द ''कालाविध'' के पश्चात् और शब्द ''वर्ष'' के पूर्व, शब्द ''तीन'' के स्थान पर, शब्द ''चार'' प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 19th December 2024

NOTIFICATION

F. No. 4555 / 4467 / XXI-B/2024.— In exercise of the powers conferred by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh and Chhattisgarh Public Service Commission, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

- 1. For sub-rule (3) of rule 6, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(3) Four percent of vacancies shall be reserved for the following persons under section 34 of "the Rights of Persons with disabilities Act, 2016":-
 - (a) One percent for the persons with "Low vision" and "blindness".
 - (b) One percent for the persons with "hard of hearing" excluding "deaf".
 - (c) One percent for the persons with "Locomotor disability", "Leprosy cured person", "Dwarfism", "Acid attack victims", "Cerebral Palsy" and "muscular dystrophy".
 - (d) One percent for the persons with Autism and multiple disabilities, from amongst persons under clauses (a) to (c) in the posts identified for each disabilities.
 - (e) Percentage of disabilities for persons with benchmark disabilities in the recruitment to the service shall be in accordance with the executive instructions/Rules/circulars of the State Government issued from time to time in this behalf:

Provided that where in any recruitment year any vacancy cannot be filled up due to non-availability of a suitable persons with benchmark disability or for any other sufficient reasons, such vacancy shall be carried forward in the succeeding recruitment year and if in the succeeding recruitment year also suitable person with benchmark disability is not available, it may first be filled by interchange among the four categories and only when there is no person with disability available for the post in that year, the Appointing Authority shall fill up the vacancy by appointment of a person, other than a person with disability:

Provided further that if the nature of vacancies in an establishment is such that a given category of person cannot be employed, the vacancies may be interchanged among the four categories with the prior approval of the appropriate Government."

2. In sub-rule (3) of rule 11, after the word "exceed" and before the word "years", for the word "three", the word "four" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, PRASHANT KUMAR BHASKAR, Deputy Secretary.